3169

शोध ग्रन्थ का सारांश

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सात अध्यायों में विभाजित है। इन अध्यायों में मेरठ जनपद में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण लोगों को कृषि, कृषि सहायक क्रियायें, गैर कृषि क्षेत्र में प्रदत्त, ऋणों का विश्लेषण किया गया है तथा साथ में सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका का परीक्षण करने का प्रयास किया है। कृषि वित्त में आने वाली समस्याओं को दर्शाते हुए भविष्य में कृषि विकास को गति प्रदान करने की रणनीति तैयार करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जो वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सहायक सिद्ध होंगे। संक्षेप में यह अध्ययन न केवल वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होगा बल्कि भावी पीढ़ी के लिए दिशा निर्देश में भी सहायक होगा।

अध्याय एक में भूमिका का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व, अध्ययन का उद्देश्य एवं परिकल्पनायें, उपलब्ध शोध साहित्य का पुर्ननिरीक्षण, अध्ययन की कार्यविधि, अध्ययन क्षेत्र की रूपरेखा, कृषि वित्त की आवश्यकता, मेरठ जनपद में वाणिज्यिक बैंकों की संरचना, मेरठ क्षेत्र में बैंकों के अग्रिम क्षेत्र आदि का वर्णन किया गया है। अध्याय दो में कृषि वित्त के श्रोत का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में परम्परागत श्रोत तथा आधुनिक श्रोत का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय तीन में कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त साख का वर्णन किया गया है। अध्याय चार में ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु वित्त व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अध्याय पांच में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख पूर्ति का वर्णन किया गया है। अध्याय छः में कृषि वित्त की वसूली एवं कृषि वित्त की समस्यायें वर्णित हैं।

अध्याय सात निष्कर्ष एवं सुझाव को समर्पित है। इस अन्तिम अध्याय में शोध कार्य का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है तथा इसी अध्याय में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। इन सुझावों से कृषि वित्त में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका बढ़ सकती है।

मेरठ जनपद में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि के विकासात्मक कार्यों एवं सहायक कार्यों के लिए ऋणों की अलग से व्यवस्था नहीं की है। एक अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र में साख की कुल आवश्यकता लगभग अगले दशक में दुगनी हो जायेगी, किन्तु वाणिज्यिक बैंक इन आवश्यकताओं के एक सूक्ष्म भाग को पूरा करने में सफल हुए हैं। इस जनपद में लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या बहुत अधिक है जिनका ऋण प्रक्रिया जटिल होने के कारण ऋण प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त ब्याज दर ऊँची होने के कारण अधिकांश कृषक बैंकों की अपेक्षा साहूकारों एवं महाजनों से ऋण लेना अधिक पसंद करते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कृषि के लिए वाणिज्यिक बैंकों से उपलब्ध ऋण न केवल अपर्याप्त एवं महंगा है बल्कि वे उत्पादन मूलक भी नहीं हैं और न समायानुसार मिल पाता है। ऐसी स्थिति में कृषि विकास और कृषकों के जीवन स्तर को उंचा उठाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की वित्त व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है।

यद्यपि मेरठ जनपद में वाणिज्यिक बैंकों ने गैर–कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कम ऋण प्रदान किये हैं फिर भी इस क्षेत्र को प्रदत्त राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। वर्ष 2013–14 में वाणिज्यिक बैंकों ने गैर–कृषि क्षेत्र को 5.21 करोड़ रूपये प्रदान किये जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 34.94 करोड़ रूपये हो गया। इस प्रकार विगत पाँच वर्षों में गैर–कृषि ऋण में लगभग 7 गुनी वृद्धि हो गयी है। फिर भी ग्रामीण लोगों की आवश्यकतानुसार

पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक एवं बैंक ऑफ इण्डिया ऐसे बैंक हैं जो कुल गैर–कृषि ऋण का 60 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति करते हैं, जबकि शेष बैंकों का हिस्सा बहुत कम है। इस जनपद में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर–कृषि क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋणों में दौराला विकास खण्ड को 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसके बाद हस्तिनापुर, रजपुरा का स्थान आता है जिन्हें कुल ऋण का केवल 14 से 15 प्रतिशत ऋण प्राप्त हुआ है।

विगत 5 वर्षों में इस जनपद के वाणिज्यिक बैंकों ने अन्य प्राथमिक क्षेत्रों जैसे ग्रामीण व्यापार एवं छोटे व्यवसायी, स्वयं नियोजन एवं रोजगार, आवास, उपभोग आदि को काफी ऋण प्रदान किये हैं। वर्ष 2013–14 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को 3.43 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये हैं जो बढ़कर 2017–18 में 59.55 करोड़ रूपये हो गया। इस प्रकार इन 5 वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों ने अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण राशि में 17 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। जनपद के वाणिज्यिक बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरियटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया प्रमुख हैं जो कुल प्रदत्त ऋण का 60 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति करते हैं। जहां तक मेरठ जनपद के विकास खण्डों का सवाल है उसमें अकेले दौराला विकास खण्ड को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण का तीन चौथाई हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसके बाद हस्तिनापुर विकास खण्ड का स्थान आता है।